National Journal of Advanced Research
www.nationaljournals.com
ISSN: 2455-216X
Received: 09-02-2026, Accepted: 12-03-2026, Published: 27-03-2026
Volume 12, Issue 1, 2026, Page No. 59-61

डिजिटल भुगतान प्रणाली का व्यापार पर प्रभाव

श्रीमति हर्षा देवानी, सौमित्र शर्मा
सहायक प्राध्यपक वाणिज्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय सकरी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

सारांश
आधुनिक युग में डिजिटल तकनीक के विकास के साथ व्यापारिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं। डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसे यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल वॉलेट के उपयोग से व्यापारिक लेन–देन अधिक सरल सुरक्षित तथा तेज हो गया है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य डिजिटल भुगतान प्रणाली का व्यापार पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना है। अध्ययन में पाया गया कि डिजिटल भुगतान ने पारदर्शिता बढ़ाई है। नकद लेन–देन को कम किया है तथा छोटे और मध्यम व्यवसायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मूलशब्द: डिजिटल भुगतान, व्यापार, यूपीआई, नकदरहित अर्थव्यवस्था, ई. कॉमर्स

वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। पहले व्यापारिक लेन–देन मुख्य रूप से नकद के माध्यम से किया जाता था, लेकिन अब डिजिटल भुगतान प्रणाली के कारण लेन–देन अधिक सुविधाजनक हो गया है। डिजिटल भुगतान प्रणाली ने न केवल व्यापार को तेज बनाया है बल्कि पारदर्शिता तथा सुरक्षा को भी बढ़ाया है। भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय तीव्र गति से डिजिटलीकरण के दौर से गुजर रही है। इस परिवर्तन की सबसे प्रभावशाली अभिव्यक्ति भुगतान प्रणाली में दिखाई देती है, जिसने व्यापार तथा विशेष रूप से खुदरा क्षेत्र के ढाँचे को गहराई से परिवर्तित किया है। जहाँ कभी भारतीय बाजारों में नकद भुगतान ही मुख्य माध्यम था, वहीं आज डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), डेबिट–क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट नेट बैंकिंग तथा QR कोड आधारित लेन–देन ने पारंपरिक भुगतान पद्धतियों की जगह ले ली है। इस परिवर्तन ने न केवल लेन–देन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया है, बल्कि उपभोक्ता और व्यापारी दोनों के व्यवहार में एक नई तकनीकी चेतना का सचार किया है।

डिजिटल भुगतान प्रणाली का अर्थ है ऐत्ता वित्तीय ढाँचा जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं के बदले मुद्रा का लेन–देन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है। यह प्रणाली केवल सुविधा प्रदान करने वाला उपकरण नहीं है, बल्कि यह आर्थिक संरचना में दक्षता पारदर्शिता और सुरक्षा का एक नया मानक प्रस्तुत करती है। भारत में डिजिटल भुगतान का उदय केवल तकनीकी प्रगति का परिणाम नहीं बल्कि नीति–निर्माताओं वित्तीय संस्थानों तथा प्रौद्योगिकी कंपनियों के संगठित प्रयात का भी नतीजा है। डिजिटल इंडिया जैसी पहल जन धन योजना तथा आधार जैसी योजनाओं ने इस दिशा में एक मजबूत नीव रखी। साथ ही फिनटेक कंपनियों तथा बैंकों के सहयोग कप अनुपालन की चुनौतियों उत्पन्न होती थी, बल्कि परिवालन लागत भी अधिक रहती थी। डिजिटल भुगतान के आगमन से इस ढाँचे में मौलिक परिवर्तन आया है। अब छोटे दुकानदार से लेकर संगठित रिटेल श्रृंखलाओं तथा ई–कॉमर्स प्लेटफॉनों तक सभी डिजिटल माध्यमों को अपनाने लगे हैं। इससे व्यापारिक पारदर्शिता गति तथा उपभोकता सुविधा वृद्धि हुई है।

डिजिटल भुगतान प्रणाली का विकास मासत में क्रमिक तथा योजनाबद रहा है। इसकी शुरुआत 1990 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (EFT) तथा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) के रूप में हुई जिसने बैंकिंग प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धन हस्तांतरण की अवधारणा को जन्म दिया। वर्ष 2010 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा इमीजिएट पेमेंट सर्विस IMPS) की शुरुआत की गई जिसने 24×7 भुगतान की सुविधा प्रदान की। यह डिजिटल कांति का प्रारंभिक चरण था जिसने मोबाइल बैंकिंग की दिशा में पहला ठोस कदम रखा। वर्ष 2016 में हुई नोटबंदी ने भारत की भुगतान प्रणाली में एक निर्णायक मोड लाया। नकदी संकट के दौर में लोगों ने डिजिटल माध्यमों को अपनाना शुरू किया तथा इसी समय यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और भीम एप (BHIM App) का आगमन हुजा जिसने डिजिटल भुगतान की आम जनता तक पहुँचा दिया।

वर्तमान में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली विश्व के अग्रणी मॉडलों में से एक बन चुकी है। NPCI के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2025 में भारत में UPM के माध्यम से लगभग 20.7 अरब लेन–देन हुए जिनकी कुल राशि ₹27.28 लाख करोड़ रही। यह आँकड़ा इस बात का साक्ष्य है कि डिजिटल भुगतान प्रणाली ने देश के व्यापार को एक नई दिशा दी है। यह वृद्धि केवल शहरी इलाकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में भी छोटे दुकानदार अब क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान स्वीकारने लगे हैं। इस प्रकार डिजिटल भुगतान ने भारतीय व्यापार संस्कृति में समानांतर समावेशिता का निर्माण किया है

डिजिटल भुगतान प्रणाली के प्रकार

सारणी क्रमांक–1

क्रं.	डिजिटल भुगतान का प्रकार	विवरण
1	यूपीआई	मोबाइल के माध्यम से तुरंत भुगतान
2	डेबिट क्रेडिट कार्ड	बैंक खाते से सीधे भुगतान
3	मोबाइल वॉलेट	ऐप के माध्यम से भुगतान
4	नेट बैंकिंग	इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग लेन–देन

अध्ययन के उद्देश्य

- डिजिटल भुगतान प्रणाली की अवधारणा को समझना।
- व्यापारिक गतिविधियों पर डिजिटल भुगतान के प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध पद्धति

यह शोध पत्र मुख्य रूप से द्वितीयक आंकड़ों (Secondary Data) पर आधारित है। डिजीटल भुगतान से संबंधित सटीक तथा सही सरकारी तथा संस्थागत स्रोत्रों द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित किए गए है। इसके अतिरिक्त विभिन्न शोध पत्रों, पुस्तकों, सरकारी रिपोर्टों तथा इंटरनेट स्रोतों का उपयोग किया गया है।

सारणी क्रमांक–2

कालखंड	प्रमुख घटनाएँ	प्रभाव
1990–2005	EFT, NEFT का प्रारंभ	इलेक्ट्रॉनिक लेन–देन की नींव रखी गई
2005–2010	इंरटनेट बैंकिग, डेबिट, क्रडिट कार्ड का प्रसार	इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की प्रारंभिक स्वीकृति
2010–2015	IMPS तथा मोबाइल बैंकिग	त्वरित 24×7 भुगतान सुविधा
2016–2020	नोटबंदीए UPI, BHIM एप का लॉन्च	डिजीटल भुगतान का जन आंदोलन
2021–2025	UPI Lite, Tap & Pay, Credit on UPI	वैश्विक स्तर पर डिजिटल स्वीकृति

(स्रोत RBI, NPCI, Digital India Dashboard, 2025)

यह विकास केवल तकनीकी प्रगति का परिणाम नहीं था, बल्कि सरकारी नीतियों तथा सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन का भी प्रतीक था। सरकार की जैम ट्रिनिटी जन धन, आधार तथा मोबाइल ने डिजिटल भुगतान के लिए आवश्यक अवसंरचना प्रदान की। सस्ते स्मार्टफोन तथा मोबाइल इंटरनेट के प्रसार ने इसे जनसाधारण के जीवन में एक व्यावहारिक आवश्यकता बना दिया। फिनटेक कंपनियों जैसे Paytm, PhonePe, Google Pay और Amazon Pay ने प्रतिस्पर्धात्मक सेवाएँ देकर उपभोक्ताओं को विकल्प उपलब्ध कराए। इसके साथ–साथ कोविड–19 महामारी ने डिजिटल भुगतान को एक सुरक्षित विकल्प के रूप में स्थापित किया, जिससे संपर्क–रहित लेन–देन को सामाजिक रूप से स्वीकार्यता मिली। डिजिटल भुगतान की इस प्रगति को ऑकड़ों के माध्यम से देखने पर इसका वास्तविक स्वरूप तथा स्पष्ट होता है।

सारणी क्रमांक–3

वर्ष	डिजिटल भुगतान वॉल्यूम (अरब में)	UPI लेन–देन (अरब में)	कुल वैल्यु (₹लाख करोड़)
2017	1.5	0.09	1.2
2019	8.0	2.9	6.0
2021	20.5	8.2	14.3
2023	35.6	12.8	21.7
2025	60.1	20.7	27.3

(स्रोत्रः NPCI product Statistics, RBI Report, PwC 2025)

प्रस्तुत आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2017 से 2025 के बीच भारत में डिजिटल भुगतान का वॉल्यूम लगभग 40 गुना बढ़ा है। इस अवधि में डिजिटल लेन–देन का मूल्य ₹1.2 लाख करोड़ से बढ़कर ₹27 लाख करोड़ तक पहुँच गया। यह न केवल तकनीकी उपलब्धि का प्रतीक है बल्कि इस बात का भी संकेत है।

डिजिटल भुगतान के इस तीव्र प्रसार ने भारत में वित्तीय समावेशन को भी नई दिशा दी है। अब दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग बैंक खातों से सीधे डिजिटल लेन–देन कर सकते हैं। इससे नकदी प्रबंधन का झंझट कम हुआ है, चोरी या नकली नोटों के खंतरे घटे हैं, तथा व्यापारिक पारदर्शिता बढी है। छोटे दुकानदारों को भी अब ग्राहकों की खरीद प्रवृत्तियों का रिकॉर्ड रखने तथा अपने व्यवसाय का आकंलन करने के नए साधन मिले हैं।

डिजिटल भुगतान प्रणाली के आर्थिक, सामाजिक तथा तकनीकी प्रभाव

डिजिटल भुगतान प्रणाली के बढ़ते उपयोग से समाज तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। इसके प्रभाव मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक तथा तकनीकी रूप में दिखाई देते हैं। डिजिटल भुगतान प्रणाली ने देश की अर्थव्यवस्था को अधिक संगठित तथा पारदर्शी बनाने में सहायता की है। नकदरहित लेन–देन के कारण कर संग्रह में वृद्धि हुई है तथा काले धन की समस्या को कम करने में मदद मिली है। इसके अलावा डिजिटल भुगतान के माध्यम से छोटे तथा मध्यम व्यापारियों को भी नए बाजारों तक पहुँचने का अवसर मिला है। ऑनलाइन भुगतान से व्यापार की गति बढ़ती है तथा आर्थिक गतिविधियाँ अधिक प्रभावी बनती हैं।

डिजिटल भुगतान प्रणाली ने लोगों की जीवनशैली तथा व्यवहार में भी बदलाव लाया है। अब लोग आसानी से मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, जिससे समय तथा श्रम की बचत होती है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच आर्थिक लेन–देन की दूरी कम हुई है। साथ ही महिलाओं तथा युवाओं को डिजिटल तकनीक के उपयोग के माध्यम से आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनने का अवसर मिला है। डिजिटल भुगतान प्रणाली के विकास के साथ नई तकनीकों का उपयोग भी बढ़ा है, जैसे मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड तथा डिजिटल वॉलेट। इन तकनीकों ने भुगतान प्रणाली को अधिक सुरक्षित तथा सुविधाजनक बनाया है। इसके अलावा फिनटेक कंपनियों के विकास से वित्तीय क्षेत्र में नवाचार (Innovation) को बढ़ावा मिला है।

सकारात्मक प्रभाव

- **लेन–देन की गति में वृद्धिः** डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से भुगतान तुरंत तथा तेजी से किया जा सकता है। इससे व्यापारियों तथा ग्राहकों दोनों का समय बचता है तथा व्यापारिक प्रक्रियाएँ अधिक कुशल बनती हैं।

- **नकद धन पर निर्भरता में कमीः** डिजिटल भुगतान के उपयोग से नकद पैसे की आवश्यकता कम हो जाती है। इससे नकदी को संभालने, गिनने तथा सुरक्षित रखने से संबंधित समस्याएँ कम हो जाती हैं।

- **व्यापार में पारदर्शिताः** डिजिटल भुगतान के माध्यम से हर लेन–देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। इससे व्यापार में पारदर्शिता बढ़ती है तथा कर व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलती है।

- **ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावाः** डिजिटल भुगतान के कारण ई–कॉमर्स तथा ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा मिला है। ग्राहक घर बैठे ही वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान कर सकते हैं, जिससे व्यापार का विस्तार संभव हुआ है।

नकारात्मक प्रभाव

- **साइबर सुरक्षा का खतराः** डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर अपराध जैसे हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी की संभावना रहती है। इससे उपयोगकर्ताओं की वित्तीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

- **तकनीकी ज्ञान की कमी:** कई छोटे व्यापारियों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में डिजिटल तकनीक का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। इस कारण वे डिजिटल भुगतान प्रणाली का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते।

- **इंटरनेट पर निर्भरताः** डिजिटल भुगतान पूरी तरह इंटरनेट पर निर्भर करता है। यदि इंटरनेट सेवा बाधित हो जाए या नेटवर्क कमजोर हो, तो भुगतान प्रक्रिया में कठिनाई हो सकती है।

निष्कर्ष

डिजिटल भुगतान प्रणाली ने आधुनिक व्यापार को अधिक सरल, तेज तथा पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से लेन–देन की प्रक्रिया तेज हुई है, नकद धन पर निर्भरता कम हुई है तथा व्यापारिक गतिविधियों में पारदर्शिता बढ़ी है। साथ ही डिजिटल भुगतान ने ई–कॉमर्स तथा ऑनलाइन व्यापार के विस्तार को भी प्रोत्साहित किया है, जिससे छोटे तथा मध्यम व्यवसायों को नए अवसर प्राप्त हुए हैं। हालाँकि, इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं जैसे साइबर सुरक्षा का खतरा, तकनीकी ज्ञान की कमी तथा इंटरनेट पर अधिक निर्भरता। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना तथा बेहतर इंटरनेट सुविधाएँ उपलब्ध कराना आवश्यक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि डिजिटल भुगतान प्रणाली का सही और सुरक्षित तरीके से उपयोग किया जाए, तो यह व्यापारिक क्षेत्र के विकास और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कुमार डॉ. उमेश (2024) डिजीटल भुगतान प्रणाली का भारतीय खुदरा व्यापार पर प्रभाव. Journal of Social Review and Development, 3(2) : पृष्ठ क्रमांक 40–47.
2. भारद्वाज डॉ. मोहित (2025) डिजीटल भुगतान प्रणाली का भारतीय खुदरा व्यापार पर प्रभावः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. Journal Of Social Review and Department, 5(1) : पृष्ठ क्रमांक 08–13
3. भट्टाचार्य डॉ. राखी (2024) डिजीटल भुगतान प्रणाली के व्यापक उपयोग का व्यक्तिगत बचत और व्यय प्रबंधन पर प्रभाव. Afr.J. Biomed. Res. 27(4) : पृष्ठ क्रमांक 14874–14877
4. ली रोमनी और ली बोरा (2024) कंम्प्यूटर इन ह्यूमन बिहेवियर. Journal computer is human behavior report, 16 : पृष्ठ क्रमांक 1–13
5. फाटक सुजीत नंदिनी (2023) अंतर्राष्ट्रीय बहुविषयक अनुसंधान पत्रिका. Inernational journal for Multidissciplinary research, 5(6) : पृष्ठ क्रमांक 1–16
6. कौर संदीप, वालिया निधि (2021) डिजीटल भुगतान प्रणाली को अपनाने में उपभोक्तओं को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण. Journal of the Gokhale Institute of Politcs and Economics, 63(3) : पृष्ठ क्रमांक 1–17
7. नाथानी साहिल, चखियार नयना और पांडेय के. शिंकी (2022) भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली के प्रति उपभोक्तओं की धारणा और इसके विकास को प्रभावित करके वाले विभिन्न कारकों पर एक अध्ययन. International Journal Of Law Management & Humanities 5(3): पृष्ठ क्रमांक 1–21
8. https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap152_e_rh.pdf
9. Economic Times. UPI records 20.7 billion transactions in festive month, 2025 Oct.
10. Government of India. BharatNet and Digital Payment Literacy Mission Reports, 2023.
11. https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/
12. from: https://www.ibef.org/industry/retail-india
13. https://rbi.org.in/Scripts/AnnualReportMainDisplay.asp